LOK SABHA

Monday, December 14, 1981/Agrahayana 23, 1903 (Saka)

The Lok Sabha met at three minutes past Eleven of the Clock

[MR. SPEAKER *in the Chair.*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

SHRI M. RAM GOPAL REDDY: Mr. Speaker, Sir, you are smiling today. What is the matter, Sir?

MR. SPEAKER: Smile is the essence of life.

Shri Janardhana Poojary.

Collaboration with United States regarding Soyabeans

*308. SHRI JANARDHANA POOJARY: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government have entered into collaboration with U.S.A. for the production, processing and utilisation of soyabeans;

(b) whether an American Soya Trade Delegation visited India during October, 1981 and held discussions in this regard; and

(c) if so, the details thereof and agreement, if any, signed?

THE MINISTER FOR AGRICULTURE AND RURAL RECONSTRUCTION AND IRRIGATION AND CIVIL SUPPLIES (RAO BIRENDRA SINGH): (a) No, Sir.

(b) In accordance with a communication received from Soyabean Processors Association of India, an American delegation from the American Soyabean Association at Missouri (U.S.A.) visited India during October, 1981 and held discussions with Soyabean Processors Association of India at Indore regarding promotion, production, processing and utilisation of soybeans.

(c) A copy of the letter of Agreement as received from the Soyabean Processors Association of India is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT—3084/81]

SHRI JANARDHANA POOJARY: May I know from the hon. Minister the steps taken to augment the stock position in the country particularly in northern India?

RAO BIRENDRA SINGH: As has been earlier stated in the House, a special soyabean project has been sanctioned for Madhya Pradesh and production is being stepped up. In Madhya Pradesh alone the area under soyabean cultivation has increased very substantially. It has almost doubled. And assistance is provided under our special soyabean production programme. As far as subsidy on seed is concerned, it is granted. Mini kits are being supplied. There is subsidy on demonstrations, training and other things.

SHRI JANARDHANA POOJARY: May I know from the hon. Minister whether there is any proposal before the Government to allow entry in trade for the big industrialists because already there is distress among the producers?

I also want to know whether Government is allowing these big industrialists to enter this trade.

RAO BIRENDRA SINGH: I do not think it is correct to say the there is distress amongst the soyabean growers. To my mind, they are getting a very good price at present. That is why soyabean cultivation is increasing.

श्री शिव कुमार सिंह ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि मध्य प्रदेश में ई० ई० सी० के सहयोग से पांच सोयाबीन सौल्वेंट-एक्सट्रैक्शन प्लान्ट चल रहे हैं इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो करार हुआ है, इसकी अवधि क्या है और इसमें हमारे देश और अमरीका का अलग-अलग हित क्या है ?

RAO BIRENDRA SINGH: We have schemes for setting up processing units.

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : अध्यक्ष जी, हिन्दी में सवाल किया गया है, तो मंत्री जी को हिन्दी में जवाब देना चाहिए ।

राव वीरेन्द्र सिंह : जब सोयाबीन की पैदावार बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो साथ-साथ उसके प्रोसैसिंग के लिए कारखाने लगाने की भी सोच रहे हैं । उसके लिए हमने योजना बनाई है, कुछ पब्लिक सैक्टर में यूनिट्स लगायेंगे और बाहर की इमदाद भी लेंगे । पहले माननीय सदस्य ने इण्डस्ट्री के मुताल्लिक सवाल किया है, तो यह पॉलिसी बात है । प्राइवेट इण्डस्ट्री के लिए भी मुमानत नहीं है हिन्दुस्तान के अन्दर, लेकिन कोशिश हमारी यह होती है कि पब्लिक अण्डरटेकिंग के जरिए से यह काम हो एग्रो इण्डस्ट्री के फिल्ड में या को-आपरेटिव्स हों, जिनको प्रैफ्रेंस दिया जाए ।

श्री शिव कुमार सिंह ठाकुर : अध्यक्ष जी मैंने दो सवाल पूछे, उन दोनों का माननीय मंत्री जी ने जवाब नहीं दिया है— एक यह कि करार की अवधि क्या है और अमरीका का हित क्या है ?

राव वीरेन्द्र सिंह : इस सवाल का इससे कोई ताल्लुक नहीं है । यह प्राइवेट दो आर्गेनाईजेशन्स हैं । उन्होंने आपस में कोई बातचीत की समझौता किया और समझौते की एक नकल हमारे पास भेज दी । इससे और ज्यादा हमें कुछ नहीं पता है ।

DR. VASANT KUMAR PANDIT : Will the hon. Minister enlighten the House as to what was the production of soyabean in Madhya Pradesh over the last three years.

अध्यक्ष महोदय : यह तो नहीं बता पायेंगे ।

DR. VASANT KUMAR PANDIT: There is a scare in Madhya Pradesh that soyabeans are not getting the prices in the market. A few minutes ago, the Hon. Minister said that they are going to set up a plant and processing and refining units. At present, the farmers are not getting a proper price for their produce, as these facilities are very limited.

अध्यक्ष महोदय : यह सवाल तो आपका ठीक है कि प्राइस मिलती है या नहीं मिलती हैं, लेकिन पहले सवाल का जवाब नहीं मिल पाएगा ।

DR. VASANT KUMAR PANDIT: At present, sufficient units are not there. I want to know whether the units are sufficient enough to take up the entire processing and refining of soyabeans?

Is there any scheme for making soyabean milk?

अध्यक्ष महोदय : राव साहब, इसके साथ-साथ यह भी बता दीजिएगा कि क्या इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिम्यूनरेटिव प्राइस फिक्स करके कोई ऐसा काम आप कर रहे हैं, जैसे कि पैडी के लिए करते हैं, व्हीट के लिए करते हैं, तो अच्छा हो जाएगा ?

राव वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब सरकार सोयाबीन के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करती है और इस वक्त कीमतें सोयाबीन की काफी ऊपर जा रही हैं । ग्राउण्ड-नट सोयाबीन और आयल सीड्स आम तौर पर जो सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स करती है, उससे ऊपर ही रही है कीमत पिछले सालों के अन्दर । इसके लिए इसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं है सोयाबीन का प्रोडक्शन हमारा बढ़ता रहा है । मध्य प्रदेश की फीगर्स मेरे पास इस वक्त नहीं है, लेकिन पिछले सालों में देश के अन्दर जो पैदावार हुई है, वह है सन् 1979-80 में 3.4 लाख टन, 1980-81 में 5 लाख टन हो गई और इस साल हमारा टार्गेट 6 लाख टन का है ।

Dam at Kishau Over River Yamuna

*309. SHRI HARISH CHANDRA SINGH RAWAT: Will the Minister of IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under the consideration of his Ministry to construct Dam at Kishau over river Yamuna; and

(b) if so, what is the estimated cost of the project?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL RECONSTRUCTION AND IRRIGATION AND CIVIL SUPPLIES (RAO BIRENDRA SINGH): (a) The Government of Uttar Pradesh have submitted a project in 1978 for construction of a Dam at Kishau in the Yamuna Basin, for providing multi-purpose benefits of irrigation, hydro power generation and flood control. This project report is under scrutiny with the Central Water Commission. Inter-States aspects of the project have also yet to be resolved.

(b) The estimated cost of the project is Rs. 459.84 crores.

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत : अध्यक्ष जी, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं—जब किसाऊ डैम की प्रपोजल के बाद डिफरेंट स्टेट्स से, 1978 के बाद जो प्रपोजल्ज आये उन को सरकार द्वारा क्लिअर कर दिया गया है, तो इस प्रपोजल के विषय में जो इतनी देर हो रही है, उस के क्या कारण हैं ?

दूसरी बात—आप के मंत्रालय में उत्तर प्रदेश के ऐसे कितने प्रोजैक्ट्स विचाराधीन हैं जिन का क्लिअरेंस होना है तथा जब आप उन प्रपोजल्ज को क्लिअर कर देंगे तो उस के बाद उत्तर प्रदेश की सिंचाई क्षमता कितनी बढ़ जायगी ?

राव वीरेन्द्र सिंह : यह प्रोजेक्ट सन् 40 से विचाराधीन है . . .

PROF. MADHU DANDAVATE: Is it 1840 or 1940?

राव वीरेन्द्र सिंह : 1940 से इस का पहली बार इन्वेस्टीगेशन काफी अर्से पहले हुआ था उस के बाद सन् 1971 में सेण्ट्रल गवर्नमेंट में फिर विचार हुआ, 1972 में इरिगेशन मिनिस्टर ने एक मीटिंग की थी, उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार से